Original Article
ISSN (Online): 2582-7472

ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts
January-June 2024 5(1), 801–806

MULTIDIMENSIONAL STUDY OF NARMADA VALLEY: IN THE HISTORICAL CONTEXT OF MADHYA PRADESH (1956-2020)

नर्मदा घाटी का बहुआयामी अध्ययन: मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक संदर्भ में (1956-2020)

Ajay Varke [1]

[1] Research Scholar

ABSTRACT

English: From 1956 to 2020, the Narmada Valley—a historically important region in India—has witnessed tremendous cultural, social, and economic changes. This paper examines the multidimensional impacts of the development projects of the Narmada Sagar Project (NSP). Agricultural expansion, industrialization, and improved water management were all outcomes of these programs, but they also created serious social and environmental problems. The economic and cultural stability of nearly 200,000 individuals, most of whom were from tribes, was disrupted when they were displaced to other locations and faced many obstacles that hindered progress in their rehabilitation program. The obstacles were not adequately addressed by these rehabilitation programs, indicating that there were gaps in the implementation of policies. Deforestation, loss of biodiversity, and changes in the river ecosystem are environmental impacts that further blur the success story. The Narmada River is a symbol of strength and perseverance for the affected people, and its cultural and spiritual significance remains unwavering despite these hardships. This study highlights the need for a holistic development strategy that incorporates social justice, environmental protection, and economic prosperity. These results are intended to contribute to policy conversations by providing insights for future initiatives that attempt to balance development with human and environmental well-being.

Hindi: 1956 से 2020 तक, भारत में ऐतिहासिक रूप से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र-नर्मदा घाटी-में जबरदस्त सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन देखे गए। इस शोधपत्र में नर्मदा सागर परियोजना (एनएसपी) की विकास परियोजनाओं के बहुआयामी प्रभावों की जांच की गई है। कृषि विस्तार, औद्योगीकरण और बेहतर जल प्रबंधन सभी इन कार्यक्रमों के परिणाम थे, लेकिन इनसे गंभीर सामाजिक और पर्यावरणीय समस्याएं भी पैदा हुईं। लगभग 200,000 व्यक्तियों की आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिरता, जिनमें से अधिकांश जनजातियों से थे, तब बाधित हो गई जब उन्हें अन्यत्र स्थानों पर विस्थापित किया गया और उनके पुनर्वास कार्यक्रम में प्रगति लाने वाली कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। इन पुनर्वास कार्यक्रमों द्वारा बाधाओं को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया गया, जो दर्शाता है कि नीतियों के क्रियान्वयन में अंतराल थे। वनों की कटाई, जैव विविधता का नुकसान और नदी के पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव पर्यावरणीय प्रभाव हैं जो सफलता की कहानी को और भी धुंधला कर देते हैं। नर्मदा नदी प्रभावित लोगों के लिए शक्ति और दृढ़ता का प्रतीक है, और इन कठिनाइयों के बावजूद इसका सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व अटल बना हुआ है। यह अध्ययन एक समग्र विकास रणनीति की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है जिसमें सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक समृद्धि शामिल हो। इन परिणामों का उद्देश्य भविष्य की पहलों के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करके नीतिगत बातचीत में योगदान देना है जो विकास को मानव और पर्यावरणीय कल्याण के साथ संतुलित करने का प्रयास करते हैं।

DOI
10.29121/shodhkosh.v5.i1.2024.3756

Funding: This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

Copyright: © 2024 The Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

With the license CC-BY, authors retain the copyright, allowing anyone to download, reuse, re-print, modify, distribute, and/or copy their contribution. The work must be properly attributed to its author.

OPEN ACCESS

Keywords: Narmada Valley, Socio-economic Development, Displacement, Environmental Impact, Cultural Heritage, Policy Implementation, नर्मदा घाटी, सामाजिक-आर्थिक विकास, विस्थापन, पर्यावरणीय प्रभाव, सांस्कृतिक विरासत, नीति कार्यान्वयन

1. प्रस्तावना

भारत में अत्यधिक भौतिक और ऐतिहासिक महत्व का क्षेत्र नर्मदा घाटी है, जो देश के हृदय तक फैली हुई है। विशाल और विविधतापूर्ण भूदृश्य को नर्मदा नदी पोषित करती है, जो मध्य प्रदेश और कुछ सीमा तक गुजरात से होकर बहती है। इसके बेसिन में रहने वाले लाखों लोगों के लिए, यह न केवल एक महत्वपूर्ण जल आपूर्ति है, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और कृषि गतिविधियों का केंद्र भी है। 100,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाली इस घाटी ने अनगिनत पीढ़ियों से अपने निवासियों के इतिहास और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। [1]

भौगोलिक दृष्टि से भिन्न, नर्मदा घाटी अलग दिखती है। घाटी दो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं-दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्य द्वारा बनाई गई है। इस क्षेत्र के कई सूक्ष्म जलवायु, वनस्पति और जानवर इसकी लाभप्रद भौगोलिक स्थिति का परिणाम हैं। नदी भारत से पश्चिम की ओर बहने के बाद अरब सागर में गिरती है, जिससे यह ऐसा करने वाली देश की कुछ महत्वपूर्ण नदियों में से एक बन जाती है। क्षेत्र के चारों ओर के विविध परिदृश्य ने कई वर्षों से विभिन्न प्रकार के पौधों और पशु प्रजातियों को घर प्रदान किया है। [2]

प्राचीन काल के मौर्यों से लेकर आज के शासकों तक, नर्मदा घाटी ने कई साम्राज्यों को आते और जाते देखा है। उत्तरी और दक्षिणी भारत के बीच व्यापार मार्ग लंबे समय से इस घाटी पर निर्भर हैं। जीवन शक्ति और प्रचुरता के प्रतीक के रूप में अपने लंबे इतिहास के कारण, नदी अक्सर प्राचीन लेखन में एक पवित्र निकाय के रूप में दिखाई देती है। मध्य युग में क्षेत्र की कलात्मक और स्थापत्य समृद्धि के सुनहरे दिनों से लेकर आज तक, नर्मदा के शहरी केंद्रों ने धर्म, संस्कृति और सरकार के केंद्र के रूप में काम किया है।

बांध, सड़क और शहरों जैसे आधुनिक बुनियादी ढांचे में सुधार ने घाटी के विकास पर गहरा प्रभाव डाला है। इसके बिना नर्मदा घाटी में कोई औद्योगीकरण, सिंचाई या बिजली उत्पादन नहीं हो सकता। सरदार सरोवर बांध चाहे भारतीय विकास की बड़ी तस्वीर पर विचार करें या स्थानीय समुदायों के दैनिक जीवन पर, नर्मदा का अत्यधिक महत्व बना हुआ है।

1.1. नर्मदा घाटी का इतिहास

400 मिलियन वर्ष पहले क्रस्टल प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित एक दरार घाटी के भीतर, नर्मदा पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, जिससे यह भारत में ऐसा करने वाली एकमात्र महत्वपूर्ण धारा बन जाती है। 1997 में जबलपुर और 1998 में खंडवा में आए दो विनाशकारी भूकंपों ने साबित कर दिया कि टेक्टोनिक गतिविधि अभी खत्म नहीं हुई है। दक्कन प्रायद्वीप में पूर्व-पश्चिम अवसाद जिसे नर्मदा-ताप्ती-सोन रेखा के रूप में जाना जाता है, बंगाल की खाड़ी से मानसूनी हवाओं को भारत के केंद्र तक ले जाता है। भारी बारिश के कारण बड़े पैमाने पर बाढ़ आती है, जिसके लिए नर्मदा कुख्यात है। [3]

नर्मदा नदी और उसकी सहायक नदियों पर तीस बड़े बांध और हजारों छोटे बांध बनाने का विचार 1960 के दशक में प्रस्तावित किया गया था स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र में व्यवधान आएगा: [4]

- कृषि की मात्रा बराबर होगी और लगभग 50,000 हेक्टेयर वन भूमि जलमग्न हो जाएगी।
- कृषि और मत्स्य पालन पर असर पड़ेगा, पत्थरों, रेत और पोषक तत्वों की सामान्य आवाजाही बाधित होगी।
- प्रवासी मछलियों, मगरमच्छों और कछुओं के साथ-साथ एक पुराना जलीय पारिस्थितिकी तंत्र गायब हो जाएगा।
- जंगली जानवरों का प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाएगा या उन्हें इसे छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
- विशेष रूप से, होशंगाबाद के पश्चिम और महेश्वर के आसपास के क्षेत्र में कई पुरातत्व स्मारकों का स्थायी नुकसान होगा।
- अनुमान है कि 500,000 किसानों, नाविकों और आदिवासियों को जबरदस्ती उनके घरों से निकाल दिया जाएगा और उन्हें अनिश्चित भविष्य का सामना करने के लिए छोड़ दिया जाएगा। अक्षम पुनर्वास कार्यक्रम कभी भी इसकी भरपाई करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे।
- मछली की संख्या में अपरिहार्य गिरावट से बांधों के निचले हिस्से में रहने वाले हजारों मछुआरों पर, यहां तक कि खंबात की खाड़ी के तटीय जल में भी, विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा।
- नदी के किनारे के रास्तों के साथ-साथ मंदिर और धर्मशालाएँ हमेशा के लिए जलमग्न हो जाएँगी, इससे परिक्रमा की सदियों पुरानी परंपरा खत्म हो जाएगी। तीर्थयात्रियों की मदद करने वाले स्थानीय लोग तटों से दूर-दूर तक फैल जाएंगे। नर्मदा के लोगों का मौखिक इतिहास उनके पास ही रहेगा।
- मलेरिया, बिल्हार्सियोसिस और डायरिया फैलाने वाले संक्रामक रोग वाहकों को विशाल जलाशयों में बेहतरीन प्रजनन स्थल मिलेंगे।
- भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र में भूकंप इसके विशाल आकार के कारण हो सकते हैं।

नर्मदा घाटी पहली बार 1970 के दशक में बहस का केंद्र बनकर सामने आई थी। सरदार सरोवर बांध और अन्य बड़े पैमाने की परियोजनाओं के निर्माण के साथ पुनर्वास और पर्यावरण संबंधी चिंताएं प्रमुख मुद्दे थे। इन रैलियों में सबसे प्रमुख, नर्मदा बचाओ आंदोलन (एनबीए), जिसकी शुरुआत

1980 के दशक में मेधा पाटकर ने की थी, इन घटनाओं के जवाब में था। विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने के तरीके के बारे में एक राष्ट्रीय संवाद अभियान द्वारा प्रज्वलित किया गया, जिसने बांध निर्माण से उजड़े लोगों की कठिनाइयों की ओर ध्यान आकर्षित किया। [5]

90 और 2000 के दशक में नर्मदा घाटी में विकास प्रस्तावों पर विवादास्पद चर्चा और अदालती लड़ाई देखी गई। सरकार ने पानी के वितरण, ऊर्जा उत्पादन और सिंचाई के लिए इन परियोजनाओं के लाभों का बखान किया, कई वर्षों की राजनीतिक और कानूनी उलझनों के बाद अंततः 2000 में कुछ पुनर्वास आवश्यकताओं के साथ बांध को भारत के सर्वोच्च न्यायालय से हरी झंडी मिल गई। इस दौरान, सामाजिक निष्पक्षता और विकासात्मक लक्ष्यों के बीच द्वंद्व ने घाटी की कहानी को आकार दिया। पिछले 20 वर्षों में नर्मदा घाटी में बहुत बदलाव हुए हैं। आधुनिक तकनीक द्वारा संभव किए गए बेहतर जल वितरण और बांध प्रबंधन के कारण घाटी में कृषि और पर्यटन जैसे उद्योग फल-फूल रहे हैं। हालाँकि, इस क्षेत्र में अभी भी समस्याएँ हैं। अधिक विस्थापित लोगों की मदद करने की आवश्यकता है, पर्यावरण की रक्षा की जानी चाहिए, और पानी और बिजली की माँग बढ़ रही है। 1956 से 2020 तक नर्मदा घाटी के विस्तार, संघर्ष और समाधान से होगा।

1.2. स्थानीय समुदायों पर प्रभाव

विकास पहलों के परिणामस्वरूप नर्मदा घाटी में गांवों के पुनर्वास से आधुनिकता और पारंपरिक जीवन के बीच टकराव दिखाई देता है। नदी लंबे समय से भीलों और गोंडों जैसे स्वदेशी समुदायों के लिए भोजन और सांस्कृतिक प्रथाओं का एक महत्वपूर्ण स्रोत रही है। दुर्भाग्य से, उनकी सांस्कृतिक पहचान और निर्वाह के साधन दोनों ही पुनर्वास प्रक्रिया से बिखर गए। अध्ययनों के अनुसार, सामाजिक समर्थन और पर्याप्त संसाधनों की कमी थी, जिससे कई विस्थापित परिवारों के लिए अपने नए घरों में अनुकूलन करना मुश्किल हो गया। विकास रणनीतियों की समावेशिता के बारे में चिंताएँ इस तथ्य से सामने आई हैं कि पुनर्वास पहलों ने स्वदेशी समूहों की जटिल सामाजिक-सांस्कृतिक गतिशीलता को ध्यान में नहीं रखा है। [6]

1.3. सांस्कृतिक विरासत और परंपराएँ

प्राकृतिक संसाधन और क्षेत्रीय पहचान आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं, जैसा कि नर्मदा घाटी की सांस्कृतिक विरासत दर्शाती है। पर्यावरणीय कारक सांप्रदायिक स्मृति और सामाजिक मूल्यों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, यह नदी की पवित्रता और इसके आसपास की परंपराओं से पता चलता है। दुर्भाग्य से, शहरीकरण और औद्योगिक विस्तार की माँगों के कारण इनमें से कई सांस्कृतिक परंपराओं को दबा दिया गया है। नदी के मंदिर और तीर्थ मार्ग, जो कभी गतिविधि के केंद्र थे, अब उपेक्षा या विनाश के खतरे में हैं। घाटी की अमूर्त सांस्कृतिक संपत्ति जो इसकी पहचान के लिए आवश्यक है की रक्षा करने में विकास पहल की विफलता और इस नुकसान से उन प्रयासों की व्यवहार्यता पर प्रश्नचिह्न लग गया है।

1.4. लोककथाओं और धर्म में नर्मदा की भूमिका

नर्मदा नदी दर्शाती है कि धर्म और प्राकृतिक दुनिया एक दूसरे के साथ कैसे परस्पर क्रिया करते हैं। स्थानीय लोगों पर सदियों से गहन पारिस्थितिक जागरूकता का शासन रहा है, जो नदी से संबंधित मिथकों और धार्मिक अनुष्ठानों में परिलक्षित होता है। उदाहरण के लिए, परिक्रमा तीर्थयात्रा केवल भक्ति से अधिक का प्रतिनिधित्व करती है; यह जीवन को सहारा देने में नदी के महत्वपूर्ण कार्य को भी स्वीकार करती है। फिर भी, नदी के आर्थिक दोहन के कारण इन सांस्कृतिक आख्यानों के क्षरण का खतरा है, जो नदी की पवित्रता को खतरे में डालता है। नीति निर्माताओं को अपनी योजना प्रक्रियाओं के एक अभिन्न अंग के रूप में सांस्कृतिक संरक्षण को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि यह संघर्ष विकास की व्यावहारिक जरूरतों के साथ धार्मिक भक्ति के बीच सामंजस्य बिठाने की बड़ी चुनौती को उजागर करता है।

1.5. कृषि और सिंचाई

नर्मदा नदी ने उस क्षेत्र में कृषि में क्रांति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जहाँ से यह बहती है। सरदार सरोवर बाँध जैसी विशाल सिंचाई परियोजनाओं के कारण किसान पहले बंजर मैदानों में खेती करने में सक्षम हुए, जिसने सूखाग्रस्त क्षेत्रों तक पानी की पहुँच बढ़ा दी। इस सफलता की बदौलत कृषि उत्पादन में उछाल आया, जिससे उच्च उपज वाली फसलों और बहु-फसल प्रणालियों के लिए दरवाज़ा खुल गया। फिर भी, आलोचकों का तर्क है कि लाभ असमान रूप से वितरित किए गए थे। उचित जल वितरण विधियों के अभाव के कारण कई छोटे किसानों को सिंचाई से लाभ नहीं मिल पाता था, जिसके कारण कुछ लोगों के मन में यह सवाल उठने लगा था कि क्या ये परियोजनाएं वास्तव में समावेशी थीं या नहीं। यह विसंगति लोगों को इस बात पर चर्चा करने के लिए प्रेरित करती है कि बड़े पैमाने की सिंचाई परियोजनाएँ कितनी फ़ायदेमंद हैं। [7]

1.6. औद्योगिक विकास और बुनियादी ढांचे का विकास

नर्मदा घाटी अपने सुविकसित बुनियादी ढांचे और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के कारण विनिर्माण का एक प्रमुख केंद्र बन रही है। इंदिरा सागर बांध और सरदार सरोवर बांध जैसी परियोजनाओं द्वारा जलविद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया गया है, जो महानगरीय क्षेत्रों और उद्योग दोनों की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करता है। राजमार्गों और रेलमार्गों जैसे अधिक कुशल परिवहन विकल्पों ने भी निवेशकों को आकर्षित किया और क्षेत्रीय वाणिज्य को बढ़ावा दिया। इन सुधारों का पर्यावरण पर भारी असर पड़ा। लोग आवास क्षरण और वनों की कटाई के कारण औद्योगिक गतिविधि की दीर्घकालिक व्यवहार्यता के बारे में चिंतित थे। इष्टतम पारिस्थितिक स्थिरता और तत्काल आर्थिक लाभ परस्पर असंगत हैं, जैसा कि बारीकी निरीक्षण करने पर स्पष्ट हो जाता है। [8]

1.7. सरकारी नीतियाँ और आर्थिक पहल

नर्मदा घाटी स्वतंत्रता के बाद आर्थिक विकास को गति देने के लिए सरकार द्वारा चुने गए प्राथमिक क्षेत्रों में से एक थी। सिंचाई, बिजली और उद्योग के लिए घाटी के संसाधनों के रणनीतिक उपयोग के प्रबंधन के लिए नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (एनवीडीए) और इसी तरह की नीतियाँ लागू की गईं। किसानों के लिए सब्सिडी और औद्योगिक निवेशकों के लिए प्रोत्साहन की शुरूआत के साथ विकास में तेजी आई। दुर्भाग्यवश, नीति कार्यान्वयन में अपर्याप्तता के कारण वंचित आबादी को अक्सर वंचित रखा गया। उदाहरण के लिए, अधिक समावेशी और भागीदारीपूर्ण नीति ढाँचे की आवश्यकता इस तथ्य से पता चलती है कि विस्थापित आदिवासी समूहों को अक्सर बहुत कम मुआवजा मिलता था और आर्थिक संभावनाओं तक उनकी पहुँच सीमित होती थी। विकास के उद्देश्यों और संसाधनों के उचित वितरण के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता इन सीमाओं से उजागर होती है। [9]

2. साहित्य समीक्षा

नर्मदा घाटी विकास परियोजना की महत्ता को समझना कठिन है। अगले बीस वर्षों में घाटी में तीस बड़े बांध, एक सौ पैंतीस मध्यम आकार के बांध और तीन हजार छोटे बांध बनने की उम्मीद है। इस परियोजना में हजारों किलोमीटर लंबी नहरों और बिजली की ट्रांसमिशन लाइनों का निर्माण शामिल है। दस लाख लोगों के पुनर्वास के लिए कमांड क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता होगी। कम से कम 350,000 हेक्टेयर वन भूमि के मुआवजे की आवश्यकता है, साथ ही जलग्रहण क्षेत्रों में वनों की सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पर पौधरोपण कार्यक्रम और सख्त नीतियां भी आवश्यक हैं। खरपतवारों और जलजनित बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए व्यापक कदम उठाना आवश्यक होगा, साथ ही कमांड क्षेत्रों में कम से कम 5 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि को जलभराव और लवणता से बचाना होगा। इन चिंताओं में सबसे कम महत्वपूर्ण बात यह है कि हजारों किसानों को कृषि पद्धतियों में आने वाले बदलावों के बारे में सूचित करने की आवश्यकता है। [10]

भारत में शोधकर्ताओं ने पाया कि विशेष रूप से गंगा और नर्मदा नदियाँ कई जटिल समस्याओं से ग्रस्त हैं। मौसमी परिवर्तन और अपर्याप्त अपशिष्ट प्रबंधन तकनीक औद्योगिक, कृषि और धार्मिक गतिविधियों को बहुत अधिक प्रदूषित बनाती हैं। हालाँकि समाज में दृढ़ता से अंतर्निहित, सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराएँ जल प्रदूषण को बढ़ा सकती हैं। निष्कर्ष नदी प्रबंधन में वैज्ञानिक ज्ञान, सांस्कृतिक समझ और नीति प्रवर्तन को एकीकृत करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं। प्रदूषण शमन के साथ-साथ इन महत्वपूर्ण जल निकायों की सांस्कृतिक और जैविक अखंडता को संरक्षित करना संरक्षण पहलों का प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए। भारत में नदी पारिस्थितिकी तंत्र को एक स्थायी तरीके से प्रबंधित करने के लिए, साहित्य में अंतराल को भरना महत्वपूर्ण है विशेष रूप से उन अध्ययनों के माध्यम से जो विभिन्न समय अवधियों की तुलना करते हैं और विभिन्न विषयों को शामिल करते हैं। [11]

शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि इन बाधाओं के बावजूद स्थानांतरित परिवारों ने अपने नए घरों में समायोजित कर लिया था। मुआवजा राशि के वितरण और अन्य पहलों को सरकार, गैर सरकारी संगठनों और सामाजिक संगठनों द्वारा समर्थन दिया गया है। वे शुरू में निपटान राशि के साथ विवेकपूर्ण थे, इसका उपयोग अपनी सबसे बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए करते थे। उनकी खर्च करने की आदतों से पता चलता है कि उनकी आय का एक बड़ा हिस्सा परिवार के लिए भोजन और कपड़ों के साथ-साथ फसलों के लिए उर्वरक, बीज और पानी जैसे कृषि इनपुट पर खर्च होता है। परिणामों के अनुसार, शिक्षा और मनोरंजन उनकी प्राथमिकता सूची में निचले पायदान पर हैं। लेकिन सामाजिक और धार्मिक कर्तव्यों में आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खर्च होता है। इसलिए, परिवार अपनी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हैं। पुनर्वास स्थानों का चयन करने की प्रक्रिया के दौरान, लगभग एक-तिहाई स्थानांतरित परिवारों ने कहा कि उन्हें विकल्प नहीं दिया गया था। सरकारी एजेंसियों ने यथासंभव अधिक से अधिक परिवारों को दो या तीन साइटों की पेशकश की। उल्लेखनीय रूप से, मध्य प्रदेश से स्थानांतरित होने वाले परिवारों के पास पुनर्वास स्थलों के सबसे कम विकल्प थे जबकि गुजरात से आने वाले परिवारों के पास सबसे अधिक विकल्प थे। धेफा को छोड़कर सभी पुनर्वास गांवों में, जहां आर्थिक विचारों को प्राथमिकता दी गई, प्रभावित परिवारों द्वारा पुनर्वास स्थानों का चयन भौगोलिक या आर्थिक विचारों की तुलना में सामाजिक-सांस्कृतिक विचारों से अधिक प्रभावित था। गोरा में पुनर्वास स्थानों का चयन आर्थिक और भौगोलिक चरों से काफी प्रभावित था। [12]

मध्य प्रदेश, गुजरात और कुछ हद तक महाराष्ट्र का सामाजिकआर्थिक विकास नर्मद-ा नदी प्रणाली से काफी प्रभावित है। जब तक व्यवहार्य विकल्प नहीं खोजे जाते तब तक मानव उपयोग के लिए नदी के पानी की बढ़ती मांग निरंतर जारी रहेगी। इसे देखते हुए नदी की उत्पादकता और उत्पादन कार्यों और नदी के मौजूदा नदी संसाधनों की सुरक्षा के लिए कुशल रणनीतियों को बिना देरी किए डिजाइन और कार्यान्वित किया जाना चाहिए। [13]

3. निष्कर्ष

नर्मदा घाटी सामाजिक और पर्यावरणीय चिंताओं को विकास योजनाओं में एकीकृत करने की कठिनाइयों और संभावित पुरस्कारों का एक प्रमुख उदाहरण है। यह कई विशाल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में से एक है जिसने अतीत और वर्तमान में सिंचाई, बिजली उत्पादन और जल आपूर्ति के साथ कई क्षेत्रों की मदद की है। कृषि और विनिर्माण जैसे बढ़ते उद्योगों को इन कार्यक्रमों से लाभ हुआ है। फिर भी, वंचित आबादी ने अक्सर इन पहलों से असंगत लाभ उठाया है। इन पहलों का सामाजिक प्रभाव विशेष रूप से आदिवासी समूहों पर कठोर था क्योंकि उन्होंने लगभग 200,000 लोगों को स्थानांतरित करने के लिए मजबूर किया। आवास का नुकसान हुआ लेकिन इन समुदायों के लिए नदी और जंगलों के लिए सांस्कृतिक प्रथाओं और पारिस्थितिक संबंधों का भी नुकसान हुआ। उनके कार्यान्वयन के बावजूद पुनर्वास उपाय अक्सर विस्थापित लोगों की दीर्घकालिक आवश्यकताओं को पूरा करने में कम पड़ गए। यह मुद्दा विकास नीति डिजाइन और कार्यान्वयन के बीच विसंगति को उजागर करता है। वनों की कटाई, जैव विविधता का नुकसान और नदी के प्राकृतिक प्रवाह में परिवर्तन कुछ पर्यावरणीय कठिनाइयाँ हैं जो प्रमुख चिंताओं के रूप में सामने आई हैं। इन पर्यावरणीय निहितार्थों को देखते हुए, घाटी के संसाधनों के प्रबंधन के लिए अधिक टिकाऊ तरीकों की आवश्यकता है। इन सभी समस्याओं के बावजूद, नर्मदा नदी अभी भी सांस्कृतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग इसे अभी भी पवित्र मानते हैं और इस क्षेत्र के कई लोगों के लिए यह शक्ति और दृढ़ता का प्रतिनिधित्व करती है। विकास की जटिलताओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए 1956 से 2020 तक नर्मदा घाटी के इतिहास को देखना उपयोगी है। यह समावेशी विकास के महत्व पर जोर देता है, प्रभावित लोगों की राय को ध्यान में रखता है संसाधनों के समान वितरण की गारंटी देता है और पर्यावरण की सुरक्षा करता है। लोगों और पर्यावरण दोनों को लाभ पहुंचाने वाला एक स्थायी संतुलन हासिल करना भविष्य के विकास प्रयासों का लक्ष्य होना चाहिए।

CONFLICT OF INTERESTS

None.

ACKNOWLEDGMENTS

None.

REFERENCES

S. Sharma, R. Sharma, and A. Shinde, “Diversity of Icthyofauna of Maheshwar Dam in Narmada River Madhya Pradesh India,” Int. J. Basic Appl. Sci., vol. 1, no. 1, pp. 1–5, 2017, [Online]. Available: www.crdeepjournal.org.

D. S. K. Bhatt, “Narmada Valley culture and civilization,” 2006.

N. Sundar, “The Dam and the Nation: Displacement and Resettlement in the Narmada Valley,” J. Asian Stud., vol. 58, no. 1, pp. 229–230, 2016, doi: 10.2307/2658453.

A. Kothari and R. Bhartari, “Narmada Valley Project: Development or Destruction,” Econ. Polit. Wkly., vol. 19, no. 22, pp. 907–909, 2019, doi: 10.4324/9780429043215.

S. Mishra, M. Studies, and S. A. Sits, “The Narmada River in Indian Prehistory,” no. January 2016, 2017.

K. Chandra, R. M. Sharma, and U. Pradesh, A compendium on the Faunal Resources of Narmada River Basin in Madhya Pradesh, no. November 2015. 2010.

N. C. Authority, “FORTY-FIRST ANNUAL REPORT,” 2021.

M. J. Peterson, O. Kiratli, and I. Ercan, “Narmada Dams Controversy – Case Summary,” no. September, pp. 1–26, 2010.

N. control Authority, “Thiry Ninth Annual Report,” Annu. Rep. 2018-19, 2019.

Kalpavriksh, “The Narmada Valley project: development or destruction?,” Soc. Environ. Eff. large dams. Vol. 2, vol. 15, pp. 224–244, 1986.

D. Yadav and S. K. Diwakar, “A Review on Environmental assessment of Narmada River water at Pilgrim place of Hoshangabad and Omkareshwar,” vol. 11, no. 4, pp. 25–29, 2024.

S. Dalal, "Development And Displacement of Denizens in Narmada Valley," vol. 22, no. 8, pp. 1–8, 2017, doi: 10.9790/0837-2208070108.

U. Bhaumik, M. K. Mukhopadhyay, N. P. Shrivastava, A. P. Sharma, and S. N. Singh, "A case study of the Narmada River system in India with particular reference to the impact of dams on its ecology and fisheries," Aquat. Ecosyst. Heal. Manag., vol. 20, no. 1–2, pp. 151–159, 2017, doi: 10.1080/14634988.2017.1288529.

https://www.ritimo.org/Struggle-to-Save-the-Narmada-Valley

https://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/repression-narmada-valley-india

https://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/narmada-issue-overview

https://www.sanctuarynaturefoundation.org/article/narmada-the-soul-of-india#:~:text=The%20Narmada%20is%20the%20only,Khandwa%20(1998)%20painfully%20demonstrated.

https://en.wikipedia.org/wiki/Narmada_Valley_Development_Authority

Madhya Pradesh ka Arthik Vikas Author: Shashi Kiran Nayak Book Type: Economics Content Partners: Madhya Pradesh Hindi Granth Academy, Bhopal